

सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी
शिक्षा के ज्ञान स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

नीरज कांडपाल

शोध छात्र

शिक्षा शास्त्र विद्याशाखा

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी उत्तराखंड

डॉ० डिगर सिंह फर्वाण

सह-प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

शिक्षा शास्त्र विद्याशाखा

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी उत्तराखंड

सारांश:

समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक-बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाओं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों में समानता के अधिकार की बात करता है और इसीलिए इसके सभी शैक्षिक कार्यक्रम इसी प्रकार के तय किए जाते हैं। ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है और नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है जिससे कि विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। इस शोध पत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक स्तर में शिक्षण कर रहे शिक्षक-शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना है। जब तक शिक्षक-शिक्षिकाओं को समावेशी शिक्षा का समुचित ज्ञान नहीं कराया जायेगा तब तक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकती है। अध्ययन हेतु जनसंख्या का चयन उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जनपद नैनीताल में अवस्थित सभी

सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के रूप में किया गया है, जिसमें से न्यादर्श स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयनविधि की सहायता से 50 सरकारी एवं 50 गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के कुल 100 शिक्षक-शिक्षिकाओंको सम्मिलित किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा शिक्षक-शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तर का आंकलन करने के उद्देश्य से स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया है तथा परीक्षणोंपरान्त प्राप्त आकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण हेतुमाध्य, मानक-विचलन एवं t-परीक्षण आदि का उपयोग किया गया है। सांख्यिकीय विश्लेषण के उपरान्त प्राप्त निष्कर्ष यह प्रदर्शित करता है कि कुछ आयामों पर तो शिक्षक-शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया किन्तु कुछ आयामों में अंतर प्रदर्शित होता है।

शब्द कुंजी: समावेशी शिक्षा, ज्ञान, प्राथमिक शिक्षा, सरकारी विद्यालय, गैर-सरकारी विद्यालय

प्रस्तावना:

शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने संजोने, विकास करने और राष्ट्रहित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हों। समावेशी शिक्षा ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ती है जिससे देश के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियां बाधक न बन पायें। शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि स्कूल शिक्षा में पहुंच, सहभागिता और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना सभी शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। शैक्षिक क्षेत्र में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) व दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने

के लिए सक्षम तंत्र को विकसित करना होगा। दिव्यांग बच्चों को प्रारंभिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए सक्षम बनाना होगा।

चूँकि किसी भी स्तर पर शिक्षण-अधिगम कार्य हेतु शिक्षक में विषय ज्ञान के साथ-साथ वातावरण सम्बंधित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है तथा विगत कुछ वर्षों से समावेशी शिक्षा एक वैश्विक विषय बना चुका है तथा हमारे देश में भी केन्द्रीय से राज्य स्तर तक निरंतर इस पर बहुपक्षीय तथा बहुस्तरीय प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा जीवन में सीखने और अपने पैरों पर खड़े होने का एक माध्यम है। आज के युग में माता-पिता बच्चों की शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा उनके बच्चों को अच्छा भविष्य प्रदान करती है। वे जीवन में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जी-जान से मेहनत करते हैं। लेकिन कई बच्चों को इसके लिए उचित समर्थन और सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। चूँकि वे दिव्यांग हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा को जोड़ा गया है। समावेशी शिक्षा समानता की बजाय समता की बात करती है। समानता का मतलब है कि सभी के साथ उनके मतभेदों की परवाह किए बिना एक जैसा व्यवहार किया जाता है। जबकि इक्विटी का मतलब है कि हर किसी को वह प्रदान किया जाता है जो उन्हें चाहिए, सफल होने के लिए या समान परिणाम प्राप्त करने के लिए।

समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य एवं विभिन्न प्रकार के शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के कक्षा समावेशन हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है।

1. शारीरिक दोषमुक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना।
2. शारीरिक दोष की दशा को बढ़ाने से पहले कि वे गम्भीर स्थिति को प्राप्त हो, उनके रोकथाम के लिये सर्वप्रथम उपाय किया जाना। बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न नवीन विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना।
3. शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का पुनर्वास कराया जाना।

4. शारीरिक रूप से अक्षमयुक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना।
5. शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना तथा सुधार हेतु सामूहिक प्रयास की तैयारी किया जाना।
6. बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनके निवारण का प्रयास करना।

शिक्षा का वह मॉडल जहां सामान्य एवं विशिष्ट छात्रों को एक साथ बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा प्रदान की जाती हो। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य छात्रों की विशेष अधिगम आवश्यकताओं की पहचान कर उनकी आवश्यकता का सम्मान करते हुए कक्षा-कक्ष शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करना है जिससे कि सामान्य छात्रों के अधिगम को सुचारू रखते हुए विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

अध्ययन की सार्थकता:

शिक्षा को किसी मनुष्य के जीवन में सामान्य जीवन कौशलों के विकास के साथ-साथ समाज में हो रहे आधुनिकीकरण की समझ का विकास करते हुए सामाजिक परिवर्तनों एवं नवीन चुनौतियों को सहज भाव के साथ स्वीकार करते हुए एक अच्छे जीवन यापन एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाने का सर्वोत्तम साधन के रूप में देखा जाता रहा है किन्तु प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिगत क्षमताओं में विविधता सभी को एक समान शैक्षिक वातावरण में समावेशित कर पाना शिक्षण-अधिगम क्षेत्र की एक व्यापक एवं सार्वभौमिक चुनौती प्रस्तुत करती है। विशेषतः जब बात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों(CWSN) की हो तो यह चुनौती असीमित सी होती प्रतीत होती है। इस प्रकार की शैक्षिक चुनौतियों के संभावित समाधान के रूप में विगत कुछ वर्षों से समावेशी शिक्षा को देखा जा रहा है जोकि प्रत्येक छात्र की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनमें सामान्य एवं व्यावसायिक सभी तरह के संभावित कौशलों के विकास में अद्वितीय भूमिका निभा रही है। प्रत्येक शिक्षा की मुख्य धुरी के रूप में शिक्षक की ही कल्पना की जाती है। अतः समावेशी शिक्षा के सफल होने के लिए भी शिक्षकों में समावेशी शिक्षा की आधारभूत समझ का

होना अत्यंत आवश्यक है जिसकी सहायता से शिक्षा के इस महत्वपूर्ण पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके एवं प्रत्येक छात्र की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा में शामिल होने में उनका सहयोग किया जा सके।

अतः शोधकर्ता द्वारा उत्तराखण्ड के कुमाऊं मण्डल के अंतर्गत जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में शिक्षक-शिक्षिकाओं के ज्ञान के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया जा गया है जिससे कि समावेशी शिक्षा के संचालन में आने वाली सम्बंधित चुनौतियों की जानकारी प्राप्त हो सके और भविष्यकी शैक्षिक योजनाओं के निर्माण में एक सार्थक निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जा सके।

अध्ययन का उद्देश्य:

- कुमाऊं मण्डल के जनपद नैनीताल के सरकारी एवं गैरसरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- कुमाऊं मण्डल के जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों के मध्य समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं:

- कुमाऊं मण्डल के जनपद नैनीताल के सरकारी और गैरसरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
- कुमाऊं मण्डल के जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष और महिला शिक्षकों के समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

शोध समस्या का सीमांकन:

- प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊं मंडल के जनपद नैनीताल तक सीमित किया गया है।

- प्रस्तुत अध्ययन कुमाऊ मंडल के जनपद नैनीतालके प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं तक सीमित किया गया है।
- प्रस्तुत अध्ययन कुमाऊ मंडल के प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं तक सीमित किया गया है।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के नैनीताल जनपद के प्राथमिक विद्यालयों की वर्तमान स्थिति पर ध्यान केन्द्रित करते हुए यह शोध अध्ययन वर्णनात्मक प्रकृति का है।

जनसँख्या

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु कुमाऊं मंडल के नैनीताल जनपद के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय तथा इनमें कार्यरत शिक्षक को शोध अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

न्यादर्श चयन

स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि की सहायता से 50 सरकारी एवं 50 गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के कुल 100 शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मिलित किया गया। शोध अध्ययन हेतु सभी विद्यालयों तथा शिक्षक- शिक्षिकाओं का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन माध्यम से किया गया है। प्रत्येक जिले से पुरुष एवं महिला शिक्षकों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया गया है:

1. समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षकों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली।

प्रदत्तों का संग्रहण

आंकड़ों के संग्रहण हेतु शोधकर्ता द्वारा सर्वप्रथम कुमाऊं मंडल के नैनीताल जिले के प्राथमिक विद्यालयों एवं उनमें सेवारत शिक्षक-शिक्षिकाओं की सूची

प्राप्त करने का प्रयास किया तत्पश्चात् इन विद्यालयों से शोध कार्य हेतु प्रयुक्त आंकड़ों का संग्रहण किया गया।

सांख्यिकीय विधियाँ

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु आंकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए केन्द्रीय प्रवृत्ति की मापों तथा t-परीक्षण तकनीक का उपयोग किया गया है। t- फलांक के आधार पर 0.05 पर सार्थकता स्तर की जांच की गयी है।

समावेशी शिक्षा का ज्ञान मापनी का निर्माण व मानकीकरण:

प्रश्नावली के निर्माण हेतु शोधकर्ता द्वारा सर्वप्रथम विविध माध्यमों से समावेशी शिक्षा से सम्बंधित सूचनाओं एवं तथ्यों का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा विविधतापूर्ण ज्ञान के परीक्षण के उद्देश्य से तथ्यात्मक, बोधात्मक एवं व्यावहारिक प्रश्नों का निर्माण करने का प्रयास किया गया। चूँकि अध्ययन का परोक्ष उद्देश्य समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षण प्रणाली को समझना भी था। अतः प्रश्नावली में कुछ सामान्य शिक्षण अभियोग्यता से सम्बंधित प्रश्नों का संकलन भी किया गया। उक्त कार्य में विषय विशेषज्ञों, प्राचीन एवं नवीन साहित्यों के साथ समय-समय पर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एवं कार्यान्वित दिशानिर्देशों का सहयोग भी लिया गया। विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझावों एवं उपरोक्त चरणों से प्राप्त संशोधनों को समाहित करते हुए समावेशी शिक्षा का ज्ञान मापनी का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया। इस मापनी में कुल 4 आयामों के अंतर्गत 39 प्रश्न रखे गये तथा प्रत्येक कथन के सम्मुख 4-4 विकल्प प्रदान किये गये। उत्तरदाता अपनी समझ के अनुसार 4 विकल्पों में से सर्वोचित विकल्प के सम्मुख (√) का चिन्ह अंकित कर अपने उत्तर का चयन करेगा। विश्वसनीयता परीक्षण हेतु प्राप्त आंकड़ों पर अर्द्ध-विच्छेदन (Split Half) तथा परीक्षण-पुनर्परीक्षण (Test-Retest) विधियों का प्रयोग करते हुए सांख्यिकी गणना हेतु पियरसन के प्रोडक्ट मोमेंट विधि की सहायता से सह सम्बन्ध गुणांक की गणना की गयी। अर्द्ध-विच्छेदन Split Half विधि द्वारा गुणांक 0.37 तथा परीक्षण-पुनर्परीक्षण (Test-Retest) विधि द्वारा गुणांक 0.89 प्राप्त हुआ जो कि मापनी की विश्वसनीयता की पुष्टि करता है।

सारणी-1
समावेशी शिक्षा का ज्ञान मापनी में विविध आयामों में वर्गीकृत कथनों का विवरण

क्र स.	आयाम	प्रश्न संख्या	कुल प्रश्न
1.	समावेशी शिक्षा से सम्बंधित शिक्षण अभियोग्यता	01 से 14	14
2.	सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में दक्षता	15 से 21	7
3.	विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के शिक्षण हेतु पाठ्य सामग्री का बोध	22 से 27	6
4.	विशेष आवश्यकता वाले छात्रों से सम्बंधित ज्ञान	28 से 39	12

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या:

शोध समस्या के आधार पर प्राप्त परिणामों की व्याख्या, विश्लेषण एवं विवेचन किया गया है। इस अध्ययन में उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मंडल के अंतर्गत जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालय एवं वहाँ पर कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तर की वास्तविक स्थिति का विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

1- कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के सरकारी एवं गैरसरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तर का तुलनात्मक अध्ययन।

सारणी-2
समावेशी शिक्षा का ज्ञान स्तर का अध्ययन

समूह	न्यादर्श	माध्य	मानक विचलन	t	सार्थकता स्तर
सरकारी	50	25.14	5.48	2.74	0.05
गैर-	50	22.68	3.16		

सरकारी					
--------	--	--	--	--	--

सारणी- 2मेंकुमाऊं मंडल के अंतर्गत नैनीताल जनपद के सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तरके तुलनात्मक अध्ययन का विश्लेषण किया गया है। सारिणी में प्रस्तुत आकड़ों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि नैनीताल जनपद के सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तरमें सार्थक अंतर पाया गया। यह अंतर सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक था। यहाँ पर t का मान 2.55 प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं की अपेक्षा गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाएं इस समस्या से अधिक प्रभावित पाए गए। अर्थात् गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाएं समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तर में अधिक उदासीन पाए गए।

2- कुमाऊं मण्डल के जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों के मध्य समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।

सारणी-3

समावेशी शिक्षा का ज्ञान स्तर का अध्ययन

समूह	न्यादर्श	माध्य	मानक विचलन	t	सार्थकता स्तर
महिला शिक्षक	50	23.88	4.61	0.06	सार्थक अंतर नहीं
पुरुष शिक्षक	50	23.94	4.63		

सारणी-3मेंकुमाऊं मंडल के अंतर्गत नैनीताल जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों में समावेशी शिक्षा का ज्ञान स्तरके तुलनात्मक अध्ययन का विश्लेषण किया गया है। सारिणी में प्रस्तुत आकड़ों

काअध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि नैनीताल जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तरमें कोई सार्थकअंतर नहीं पाया गया।यहाँ पर t का मान 0.06 प्राप्त हुआ।यद्यपिपुरुष एवं महिला शिक्षकों मेंसमावेशी शिक्षा का ज्ञान स्तरके माध्य एवं मानक विचलन में अंतर था तथापि यह अंतर सांख्यिकीयदृष्टिकोण से सार्थक नहीं पाया गया।इससे यह स्पष्ट होता है किपुरुष एवं महिला शिक्षकलगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित पाए गए।

निष्कर्ष:

अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के सरकारी एवंगैरसरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओंके मध्य समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तर का तुलनात्मक अध्ययनकरना था।अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि नैनीताल जनपद में सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तरसार्थक अंतर था इससे यह स्पष्ट होता है किसरकारी की अपेक्षा गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाएं में यह समस्या अधिक व्याप्त थी।नैनीताल जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकोंके समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तरकोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया इससे यह स्पष्ट होता है किप्राथमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकलगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित पाए गए।

शैक्षिक निहितार्थ

अध्ययन से प्राप्त परिणाम वर्तमान परिदृश्य में समावेशी शिक्षा की संकल्पना को स्थापित करने के क्रम में सहयोगी हो सकते हैं तथा समावेशी शिक्षा के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ उसकी व्यावहारिक समझ के विकास की ओर भी विचार करने के लिए शिक्षा नियोजकों को प्रेरित किया जा सकता है। सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी महिला एवं पुरुष शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विद्यालयी गतिविधियों में आवश्यक नवाचारों के अनुपालन द्वारा विद्यालय में समावेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त वातावरण निर्माण

कीसंकल्पना को साकार किया जा सकता है क्योंकि विद्यालयों में समावेशी वातावरण निर्माण का प्रमुख घटक शिक्षक-शिक्षिकाएं ही होते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बच्चों के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। अतः समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षकों में आवश्यक योग्यता का विकास किया जाने पर भी विचार किया जा सकता है तथा प्राथमिक विद्यालयों में वैयक्तिक विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता तथा मानसिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षकों की व्यवस्था तथा इनके लिए आवश्यक शैक्षिकसंसाधनों एवं शैक्षिक उपकरणों की समुचित व्यवस्था कर गुणवत्तापरक शिक्षण अधिगम को बढ़ावा दिया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची:

डिसेबल पर्सन इन इंडिया: ए स्तैतिस्तिकल प्रोफाइल (2016)

<https://www.mha.gov.in>, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (2016)

<https://www.education.gov.in>, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

एजुकेशन फॉर आल: टुवर्ड्स क्वालिटीविथ इक्विटी(2016)

देवी कुसुम, समावेशन शिक्षा में अध्यापकों के उत्तरदायित्व एवं भूमिका: एक समीक्षा।

निमांटे दिता, समावेशी शिक्षा के लिए उनकी योग्यताओं पर शिक्षकों का परिप्रेक्ष्य।

कुमार विरेन्द्र, वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं प्रमुख चुनौतियां।

Farswan, D. S. (2023). National Education Policy 2020 and Teacher Education in India. Mukt Shabd Journal, 13(1), 770-782.

Farswan, D. S. (2023). NEP 2020 and inclusive education in India. JOURNAL OF XI' AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY 16(1), 581-591.